

## प्रेस विज्ञप्ति

रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक व मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

18 सितंबर, 2017

**“न रोटी, न रोजगार – चारों ओर भ्रष्टाचार – भाजपा सरकार ने किया हरियाणा के नौजवानों से धोखा व विश्वासघात”**

खट्टर सरकार बनी 'पेपरलीक सरकार', लाखों युवाओं का भविष्य अधर में केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकारों ने सत्ता हथियाने के लिए देश-प्रदेश के युवाओं को लोक-लुभावने सब्जबाग दिखाए। मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वायदा कर डाला। खट्टर सरकार ने प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार या फिर रोजगार के बदले 6,000 रु. व 9000 रु. प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा कर डाला। पर तीन साल में हासिल हुआ – धोखा तथा विश्वासघात।

3 वर्ष बीतने के बाद हरियाणा के नौजवान के पास न रोटी है और न रोजगार तथा भविष्य बीच अधर है। नौकरियों में घालमेल और गोलमाल चरम सीमा पर है व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पूरे गड़बड़झाले में खट्टर सरकार कभी स्वयं को असहाय बताती है और कभी शासन की हेराफेरी में संलिप्तता साफ नजर आती है।

**खट्टर सरकार ने दीं तीन साल में मात्र 7,886 नौकरियां और नौकरी से निकाले लगभग 20,000 कर्मचारी**

तीन वर्ष में HPSC व HSSC के माध्यम से खट्टर सरकार ने लगभग 7,886 नई नौकरियां ही लगाईं (HPSC में 1160 और HSSC में 6,726)। हरियाणा के नौजवानों के साथ घोर अन्याय का इससे पुख्ता सबूत और कोई नहीं हो सकता।

इसके विपरीत 20,000 के करीब युवाओं को या तो नौकरी से निकाल दिया या फिर नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया। 3581 गेस्ट TGT अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। 3500 गेस्ट JBT अध्यापकों को नौकरी से निकालने की तैयारी है, जिनमें पानीपत और यमुनानगर से 100 अध्यापकों को बर्खास्त किया जा चुका है। 2300 कंप्यूटर अध्यापकों व 2622 कंप्यूटर लैब असिस्टेंट को दो बार नौकरी से बर्खास्त कर, जुलाई, 2017 में एक व्यापक आंदोलन के बाद वापस लिया गया। NHM व NRHM में काम कर रहे लगभग 1500 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा PWD, जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, वन विभाग तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में तदर्थ आधार पर काम करने वाले 5000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया।

सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार युवाओं की रोटी व रोजगार छीनने का काम कर रही है।

## ‘खट्टर सरकार बनी पेपरलीक सरकार’

शिक्षा व रोजगार में होता आए दिन का भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा अब आम बात हो गई है। HPSC, HSSC, पुलिस भर्ती, HBSE, HTET, AIPMT, NEET के पेपरलीक घोटालों ने युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया है।

खट्टर सरकार के शासन में 13 बड़े पेपरलीक घोटाले हुए – (I) ऑल इंडिया पीएमटी पेपरलीक घोटाला (मई, 2015), जिसमें लगभग 100 करोड़ के गबन का इल्जाम सामने आया। (II) HBSE बारहवीं कक्षा इंग्लिश पेपरलीक घोटाला (मार्च, 2015) (III) HTET पेपरलीक घोटाला (नवंबर, 2015)। (IV) केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपरलीक घोटाला (अक्टूबर, 2015, रेवाड़ी)। (V) क्लर्क भर्ती पेपरलीक घोटाला (दिसंबर, 2016), जिसमें भाजपा नेता के पानीपत के स्कूल का नाम सामने आया। (VI) एक्साईज इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला (दिसंबर, 2016)। (VII) HBSE नौवीं कक्षा हिंदी पेपरलीक घोटाला (मार्च, 2017)। (VIII) एनईईटी पेपरलीक घोटाला (मई, 2017)। (IX) बी.फार्मैसी पेपरलीक घोटाला (जुलाई, 2017)। (X) HCS (Judicial भर्ती पेपरलीक घोटाला) (जुलाई, 2017)। (XI) एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला (जुलाई, 2017)। (XII) कंडक्टर भर्ती पेपरलीक घोटाला (सितंबर, 2017)। (XIII) असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज काडर पेपरलीक घोटाला (फरवरी, 2017)

इस प्रकार से संपूर्ण सरकारी तंत्र भारी शक व संदेह के घेरे में है, फर्जीवाड़े तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, व पारदर्शिता लागू करने के वायदे के साथ सत्ता में आई सरकार ने युवाओं के साथ सरेआम धोखा किया है।